रॉ शुगर सब्सिडी पर केंद्र ने मिलों को दिया 'गच्चा'

[जयश्री भोंसले | पुणे]

चीनी मिलें अप्रैल और मई में रॉ शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी की तस्वीर साफ करने की मांग कर रही हैं। 3,300 रुपये प्रति टन की सब्सिडी फरवरी और मार्च महीने के लिए दी गई थी और इसे हर दो महीने पर रिवाइज्ड किया जाना था। रुपये के मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसे रिवाइज करना था।

इंडस्ट्री के दिग्गजों का कहना है कि शुगर एक्सपोर्ट के फिजिकल मूवमेंट में देरी से डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के दाम पर असर पड़ सकता है, जिसमें फरवरी के बाद से लगातार तेजी आ रही है। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी को रॉ शुगर प्रॉडक्शन के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया था। यह स्कीम 2013-14 और 2014-15 के लिए लाई गई थी। यह स्कीम शुगर इंडस्ट्री को पुराना स्टॉक कम करने में मदद करने के लिए पेश की गई थी। इससे उनके कैश फ्लो में बढ़ोतरी होती और वे समय पर गन्ना किसानों को पैसा दे पाती। इंसेंटिव का ऐलान फरवरी और मार्च 2014 के लिए किया गया था।

सब्सिडी की रकम 3,300 रुपये प्रति टन तय की गई थी। इसे हर दो महीने पर रिवाइज किया जाना था। 28 फरवरी 2014 के गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 3,300 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दो महीने के लिए दी जा रही है। इसके बाद एक्सचेंज रेट को देखते हुए इसमें संशोधन किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने रिवाइज्ड सब्सिडी की घोषणा नहीं की है। इसका ऐलान अप्रैल की शुरुआत में ही हो जाना चाहिए था। इंसेंटिव के ऐलान में देरी के चलते इंडस्ट्री को शुगर एक्सपोर्ट का फिजिकल मूवमेंट प्रभावित होने का डर सता रहा है। यूपी में एक प्राइवेट शुगर मिल के मालिक ने बताया कि एक्सपोर्ट में देरी से मिलों के कैश फ्लो पर नेगेटिव असर होगा। इससे उन्हें गन्ना किसानों को भुगतान करने में दिक्कत होगी। देश में क्रशिंग सीजन खत्म होने को है। इसके बावजूद रॉ शुगर एक्सपोर्ट के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए जा रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर के मौजूदा शुगर सीजन में अब तक भारत ने 19 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से 8.5 लाख टन रॉ शुगर है। मौजूदा सीजन में कुल एक्सपोर्ट 25 लाख टन रहने की उम्मीद है। इसमें से रॉ शुगर 11 से 12 लाख टन रह सकता है। 28 फरवरी को जब इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया था, तब डॉलर के मुकाबले रुपया 62.44 के लेवल पर था। उसके बाद से भारतीय करेंसी में मजबूती आई है। रुपये में मजबूती के चलते सब्सिडी की रकम 3,300 रुपये से ज्यादा हो गई है, लेकिन मिनिस्ट्री कैबिनेट की मंजूरी के बगैर इसे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में अप्रैल और मई के लिए भी सब्सिडी 3,300 रुपये प्रति टन रह सकती है।

- **केंद्र सरकार** ने 28 फरवरी को रॉ शुगर प्रॉडक्शन के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया था
- **यह स्कीम** 2013-14 और 2014-15 के लिए लाई गई थी। यह स्कीम शुगर इंडस्ट्री को पुराना स्टॉक कम करने में मदद करने के लिए पेश की गई थी

Economic Times